शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 जुलाई 2017
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

संपादकीय

विश्वविद्यालयों में बोलियों के लिए नागरी लिपि विभाग

डॉ.पुष्पेंद्र दुबे

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के समस्त विश्वविद्यालयों को देवनागरी लिपि के संबंध में पत्र जारी किया है। इस पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालयों में देवनागरी लिपि का विभाग खोलने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किया है। इस पत्र में कहा गया है कि जिन बोलियों के लिए कोई निर्धारित लिपि नहीं है उन बोलियों के मौलिक रूप को देवनागरी लिपि में संरक्षित करने के लिए विश्वविद्यालयों में देवनागरी लिपि का एक विभाग बनाया जाना चाहिए। प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रारूप में विश्वविद्यालय से हिन्दी विभाग की जानकारी, अनुमोदित पद, पदों का विवरण, हिन्दी विभाग की आधारभूत संरचना, तकनीकी संसाधन और सुविधाओं का ब्यौरा मांगा गया है। विश्वविद्यालयों से यह जानकारी भी मांगी गयी है कि विश्वविद्यालय ने उसके परिक्षेत्र में बोलियों से संबंधित शोध किया है। कौन-सी ऐसी बोलियां हैं जिनके पास अपनी लिपि नहीं है। इसके अंतर्गत बोली का नाम, किन क्षेत्रों में बोली जाती है और बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि सभी भारतीय भाषाएं देवनागरी लिपि को अपनायें और उसके लिए उनकी प्रेरणा से सन् 1961 में सभी मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई थी। जिसमें इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था।

आचार्य विनोबा भावे की प्रेरणा से 17 अगस्त 1975 को गांधी स्मारक निधि के तत्वावधान में 'नागरी लिपि परिषद' की स्थापना की गयी। नागरी लिपि परिषद के प्रचारार्थ एक पत्रिका 'नागरी-संगम' निरंतर प्रकाशित हो रही है। नागरी लिपि परिषद के प्रयासों से बोडो भाषा ने नागरी लिपि को अपनाया। इसी प्रकार संताली लिपि भी देवनागरी लिपि में आ गयी है। श्री मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति इन्दौर में 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस पर 'नागरी लिपि और मातृभाषा' विषय पर परिसंवाद आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रातों के वक्ताओं ने उनके द्वारा बोली जाने वाली मातृभाषा को देवनागरी लिपि में लिखने के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए।

हाल ही श्री मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति इन्दौर ने एक प्रस्ताव द्वारा नागरी लिपि प्रकोष्ठ का गठन किया है। समिति के प्रधानमंत्री श्री सूर्यप्रकाश चतुर्वेदी हैं। इस प्रकोष्ठ के निदेशक डॉ.राजेंद्र मिश्र और संयोजक डॉ.पुरुषोत्तम दुबे को मनोनीत किया गया है। डॉ.शोभा चतुर्वेदी और डॉ.पुष्पेंद्र दुबे इस प्रकोष्ठ के सह-संयोजक हैं। महात्मा गांधी ने साहित्य परिषद् मद्रास की दूसरी बैठक के सभापित पद से अपने वक्तव्य में कहा था, "मैं तजुर्बे के साथ आपसे कहता हूं कि दूसरी देषी भाषा सीख लेना कोई मुष्किल बात नहीं। लेकिन इसके लिए एक सर्वमान्य लिपि का होना आवष्यक है।...हम जो राष्ट्रीय एकता हासिल करना चाहते हैं, उसकी खातिर देवनागरी का सामान्य लिपि स्वीकार करना आवश्यक है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। बात सिर्फ यह है कि हम अपनी प्रांतीयता और संकीर्णता छोड़ दें।"

बहरहाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान नागरी लिपि की ओर गया है तो निश्चित ही भविष्य में शीघ्र ही इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे।